मजदूरों का अपना कोई देश नहीं होता ।

दुनियां के मजदूरो, एक हो ।

फरीदाबाद मजदूर समाचार

मजदूरों की मुक्ति खुद मजदूरों का काम है ।

दुनियां को बदलने के लिए मजदूरों को खुद को बदलना होगा ।

RN 42233 पोस्टल रजिस्ट्रेशन L/HR/FBD/73

नई सीरीज नम्बर 42 | दिसम्बर 1991 | 50 पैसे

29 नवम्बर को "हड़ताल"

सरकारी नौकरी की पोल और पूंजीवादी उठा-पटक

इस समय प्रायवेटकरण के शोर शराबे में हमारा यह कहना है कि सामाजिक जीवन में सरकार का महत्व बढ रहा है. कुछ अजीब सा लग सकता है पर यह एक हकीकत है । दरअसल जिसे आज प्रायवेट कहा जाता है वहाँ सरकारी कन्ट्रोल अप्रत्यक्ष मात्र है पर कम प्रभावी नहीं है । इसका बुनियादी कारण उत्पादक शक्तियों के स्तर का बजह से मालिकाने में आया परिवर्तन है । और फिर, हर देश में पुलिस-फौज-जेल-कोर्ट-प्रशासन जैसे फिजूल के काम करने वाले कर्मचारियों की गिनती तो बढ़ती जा रही है, जीवन की भौतिक आवश्यकताओं अनाज, कपड़ा, दवाई, सीमेन्ट, स्टील के प्रोडक्शन तथा शिक्षा, ट्रान्सपोर्ट संचार जैसे मनुष्यों के लिये उपयोगी क्षेत्रों में भी सरकार का वजन बढ़ रहा है । यह वास्तविकता मजदूर आन्दोलन के लिये, समाज व्यवस्था में क्रान्तिकारी परिवर्तन के लिये सरकारी क्षेत्र के वरकरों की भूमिका को अधिकाधिक महत्व पूर्ण बना रही है । प्रोडक्शन प्रोसेस में आ रहे बदलाव अन्य क्षेत्रों के लोगों की ही तरह वैज्ञानिकों-डाक्टरों आदि को भी शिल्पियों से टेक्नीकल/इन्डस्ट्रीयल वरकरों में बदल कर क्रान्तिकारी मजदूर आन्दोलन के लिये विस्तृत बौद्धिक स्रोत की रचना कर रहें हैं । लेकिन नई शक्तियों के एक बेहतर समाज व्यवस्था की रचना में अग्रसर होने की राह में सस्कार और विशेषकर सरकारी नौकरी को पक्की सुरक्षित मानने के भ्रम रुकावट हैं । इसलिये ब्राजील-इग्लैंड-पोलैंड-रूस में बड़े पैमाने पर सरकारी वरकरों की छँटनी का हमने अपने अंक २५ में जिक्र किया था । उस समय, जुलाई 1990 में हमने लिखा था; "भारत में भी जब-तक कोई-न-कोइ मन्त्री सरकारी खर्चे में कटौती का बकालात करता रहता है । सरकारी सस्थाओं के प्रायवेटकरण की आवश्कताओं की सुगबुगाहट भी अब यहां होने लगी है । पर पूंजीवादी जनतन्त्र का नाटक इस समय यहाँ उस नाजुक स्थिति में है कि "लोकप्रिय" होने की मची होड़ में बड़े पैमाने पर सरकारी वरकरों की छँटनी वाले "अलोकप्रिय" कदम के लिये कोई नेता-मन्त्री इस समय खुल कर सामने नहीं आ रहा । पर यह टेम्परेरी स्थिति है । पूंजीवादी जनतन्त्र के अजूबे में भी अर्थव्यवस्था का बढ़ता संकट विभिन्न किस्म की खाश करके हिन्दुवादी पूंजीवादी एकतन्त्रीय शक्तियों को मजबूत कर रहा है । लड़-खड़ाती अर्थव्यवस्था को सम्भालने के लिये झटके का रूप और समय तय होने वाली बात ही बाकी बची है । "

हमारी उपरोक्त बातों के साल-भर बाद ही सरकारी वरकरों व कर्मचारियों के सिर कलम करने की सरकारी घोषणा यहाँ होने लगी । सरकारी नौकरी करने वालों के पैरों तले की जमीन खिसकने लगी । जिसे ठोस टेक माना जा रहा था वह रेत की दीवार निकली । रोजी-रोटी पर मँडरा रहे खतरे ने आम-तौर पर डर को ही उभारा-इस डर को भुनाने में लगी पुंजीवादी पार्टियों का ऊल-जलूल प्रचार सरकारी नौकरी करने वालों में दशहत पैदा कर रहा है । 29 नवम्बर की "हड़ताल" की ब्यापकता व कमजोरी का यह एक महत्वपूर्ण कारण रहा । वैसे बैंक-बीमा क्षेत्र में वास्तव में बहुत बड़े पैमाने पर छँटनी की सम्भावना है और इस क्षेत्र में २९ नवम्बर को वास्तव में हड़ताल हुई—यहाँ अपनी नाक तक देखने की बहुत अच्छी क्षमता के साथ ही नाक से आगे नही देखने की कमी भी उजागर हुई ।

29 नवम्बर की घटना दरअसल मजदूरों की हड़ताल से अधिक पूंजीवादी गुटों के बीच एक उठा-पटक थी । सरकारी मनेजमेन्ट को प्रमुखता देने वाले नेहरूवादी समाजबाद को काँग्रेस ने साँप द्वारा केंचुली उतारने की तरह अपने से अलग कर दिया—रूस आदि की हाल की घटनाओं की वजह से इस पर बराये नाम की चीं चां का स्वर भी बहुत धीमा रहा है । रूस-चीन-पूर्वी यूरोप की घटनाओं से सुन्न पड़े यहाँ के नकली कम्युनिष्ट औपचारिकता निभाने, कर्मकाण्डी मन्त्र जपने तक स्वयं को सीमित रखे थे । सरकारी मैनेजमेन्टों-पूंजीवादी बुद्धिजीवियों के एक धड़े के तेवरों और सरकारी कर्मचारियों-वरकरों के डर में उन्हें इस्तेमाल करने-भुनाने योग्य मैटेरियल नजर आया । शासक बर्ग में अपनी कमजोर पड़ रही पोजीशन को मजबूत करने के लिये सी पी आई-एटक, सी पी एम-सीटू आर यस पी-यूटी यूसी, एस यू सी आई-यूटी यूसी (लेसा) आदि ने 29 नवम्बर वाली डुगडुगी बजाई । इधर हिन्दूवादी भाजपा पूंजीवादी मंच पर केन्द्रीय रोल लपकने की स्थिति में आ गई है । इसलिये नई आर्थिक नीति के नाम पर काँग्रेस द्वारा भाजपा-बी एम एस के माफिक कदम उठाने और नकली कम्युनिष्टों द्वारा इस पर छाती पीटने वाले माहौल में भाजपा-बी एम एस "न्यूट्रल" रही । वैसे, काँग्रेस की नई नीति और जन संघ-भाजपा की पुरानी नीति में "प्रायवेट" शब्द ही साँझा है—"निराकार" बनी पूंजी के इस दौर में "प्रायवेट" का अर्थ पिछली सदी में "साकार" पूंजी के दबदबे वाले दौर से बहुत भिन्न है पर हिन्दूवादी कूये के मेडक और गोल-मटोल काँग्रेसी, दोनों ही इसके बारे में अन्धेरे में हैं । रही जनता दल-एच एम एस की बात तो यह लोग न तीन में हैं न तेरह में । इनके मामले में 29 नवम्बर की घटना मजाक प्रहसन था । वैसे, राजीव के वित्त मन्त्री वी पी सिंह ने नेहरूवादी समाजवाद की केचुली उतारनी शुरू की थी, नेहरू भगत नरसिम्हा राव ने उसे पूरी तरह उतार फेंका है । वी पी सिंह सरकार द्वारा बनाई एक कमेटी ने ही 1995 तक 25 लाख रेलवे वरकरों में से दस लाख की छँटनी की सिफारिश की है—राव सरकार इस पर विचार कर रही है । और नकली कम्युनिष्टों के एक अन्य हीरो, मुलायम सिंह की सरकार ने भाँडों की वाह-वाही के दौर में उत्तर प्रदेश सरकार के घाटे में चल रहे उद्यमों को बन्द करने-उनका प्रायवेटकरण करने का नीति निर्णय लिया था व उस पर अमल भी आरम्भ कर दिया था ।

प्रायवेटकरण-सरकारीकरण को अक्सर ऐसे पेश किया जाता है आया वे परस्पर बिरोधी हों । वास्तव में आज के प्रायवेट व सरकारी कारखानों में उन्नीस-बीस का ही अन्तर है । पूंजीवादी मैनेजमेंट के यह दो रूप मात्र हैं । एक से दूसरे में रूपान्तरण दरअसल छटनी-वर्कलोड में बृद्धि बेतन कटौती आदि पर परदे डालने के लिये किया जाता है इस सिलसिले में इंगलैंड-फ्रास आदि में प्रायवेट का सरकारीकरण और सरकारी का प्रायवेटकरण एक देखी जानी चीज बन चुकी है । लेकिन यहाँ अब तक प्रायवेट के सरकारीकरण की प्रक्रिया ही देखी गयी थी इसलिये सरकारी के प्रायवेटकरण ने कईयों को चकरा रखा है । इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने के प्रयास में हमने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपनी डाला सीमेन्ट फैक्ट्री डालमिया ग्रुप को सौंपने के घटनाक्रम का सहारा लिया था । डाला में पुलिस गोलीबारी में बहे मजदूरों के खून के मजदूर आन्दोलन के लिये सबकों पर जुलाई 1991 में विचार करते समय हमने लिखा था । "कुछ समय पहले तक दुनिया भर में सरकारीकरण को पूंजीवादी संकटों की रामबाण दबा पेश किया जाता था । पुलिस फौज के एक क्रूर तन्त्र के स्थान पर उससे भी क्रूर पुलिस-फौज के तन्त्र को स्थापित करने के लक्ष्य वाले नकली कम्युनिस्ट इसके बड़बोले बकील थे ..... राज्य-पूंजीवाद को समाजवाद और सरकारी उद्योगों को सार्वजनिक उद्योग-पब्लिक सैक्टर कहने वाले बदमाशों व बेवकूफों को रूश-चीन आदि की हाल की घटनाओं ने हक्का-बक्का सा कर दिया है । इन हालात में प्रायवेटकरण को अचूक तावीज बताने बाले प्रबचनों का आज बोलबाला हो गया है ।

"..... वास्तव में प्रायवेटकरण अथवा सरकारीकरण के सिलसिले द्वारा किसी देश में कार्यरत पूंजी इकाई द्वारा तत्काल राहत महसूस करना, यानि पूंजीवादी होड़ में उस द्वारा कुछ दम-खम हासिल करना तभी हो पाता है जब इन कारवाईयों के दौरान वह मजदूरों की बड़े पैमाने पर छँटनी, बर्कलोड में भारी बढ़ोतरी तनखा में कटौती, सहुलियतों में कमी आदि के द्वारा अन्य देशों में कार्यरत पूंजी से कम लागत पर अधिक प्रोडक्शन हासिल कर पाती है । लेकिन चूँकि हर देश में पूंजी के नुमाइन्दे यही करने की कोशिशों में जुटे रहते हैं । इसलिये जल्दी ही ऐसी ही राहत खत्म हो जाती है । "

अन्त में आइये 29 नवम्बर की घटना के सम्बन्ध में एक दूसरे के बिरोधी पूंजीवादी गुटों के दलीलों के लुब्बो लुबाव पर गौर करें । नई आर्थिक व औद्योगिक नीति का पक्ष धर कहतें हैं कि देश की लड़खड़ा रही अर्थव्यवस्था को सम्भालने, देश को मजबूत करने के लिये यह जरूरी हैं—कड़वी है तो भी देश की सेहत के लिये यह दवाई जरूरी है । और इन नीतियों के विरोधी पूंजीवादी गुट कहते हैं कि यह नीतियाँ देश की अर्थ व्यवस्था को तबाह कर देंगी-नई नीतियों द्वारा सरकार ने देश को आई एम एफ-वर्ल्ड बैंक-बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को बेच दिया है । पूंजीवादी गुटों की ऐसी दलीलों का खण्डन करने के प्रयास में हमने जुलाई 1990 के अक में लिखा था; "पूंजीवाद में उत्पादन मानवों की जरूरत को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता बल्कि मंडी में बिक्री के के लिये प्रोडक्शन होता है बुनियादी तौर पर आज उत्पादन देशों के आधार पर संगठित है और मारकेट है विश्व मन्डी । ऐसे में किसी देश की अर्थव्यवस्था कमजोर होने का मतलब यह है कि उस देश का प्रोडक्शन विश्व मण्डी में अन्य देशों के मुकाबले टिक नहीं पा रहा । यानि, उस देश में पैदा किया गया सामान अन्य देशों की तुलना में मँहगा है ।... इसलिये ऐसे में किसी देश को मजबूत करने का पहला मतलब है उस देश में प्रोडक्शन की लागत को कम करना । लेकिन उत्पादन खर्च कम करने का अर्थ है कम मजदूरों से कम मजदूरी पर अधिक प्रोडक्शन लेना । इसलिये किसी देश को मजबूत करने का मतलब यह है कि उस देश के मजदूर कम तनखा लें और ज्यादा काम करें । देशभक्ति का मजदूरों के लिये मतलब पर यह है कि वे पूंजीबादी गुटों की होड़ में "अपने" पूंजीवादी गुट की बेदी पर अपना रक्त चढ़ायें । "

असल में मंडी के लिये उत्पादन की जगह अब प्रोडक्शन को मानवों के लिये जो योजनाबद्ध करना जरूरी हो गया है । इसके लिये विश्व मन्डी के स्थान पर विश्व मानव समुदाय की स्थापना करना जरूरी है । अतः इस कार्य को धुरी बना कर ही सरकारीकरण अथवा प्रायवेटकरण की आड़ में होने वाले हमलों का मजदूर माकूल जबाब दे सकते हैं, ऐसे हमलों को पुरातत्व बिभाग के लिये एक और विषय बना सकते हैं ।

संपर्क मजदूर लाइब्रेरी, आटोपिन झुग्गी, बाटा चौक के पास, एन. आई. टी. फरीदाबाद 121001

विक्टोरा टूल्स

प्लाट नम्बर 46 सैक्टर 25 स्थित विक्टोरा टूल्स परिवार की मैनेजमेन्ट वाली फैक्ट्री है। यहाँ के मजदूर रोज की गाली-गलौज, हर समय सिर पर खड़े रहने, छोटी-छोटी सहूलियतों के लिये तड़पाने वाले फैक्ट्री के माहौल से बहुत तंग थे। जुलाई में एक मजदूर को हिसाब से जो बनते थे उससे कम पैसे दिये जाने और गाली-गलौज व धक्के मारने की घटना ने मजदूरों में हलचल पैदा की। चार-पाँच दिन के विचार-विमर्श के बाद 17 जुलाई को वरकरों ने मीटिंग की। संगठन बना और अगले दिन से ओवरटाइम बन्द करने तथा डेजिगनेशन के हिसाब से काम करने का फैसला किया गया। मजदूरों ने अपने फैसलों पर अमल किया एक-एक करके मजदूरों से पूछा गया, पहले की तरह काम करने को कहा गया पर मजदूरों ने एकता बनाये रखी और अपने फैसलों पर डटे रहे। काफी पापड़ बेलने के बाद मैनेजमेन्ट एक वरकर को फोड़ने में कामयाब हुई—23 अगस्त को मजदूरों को पुलिस और जेल की धमकियाँ दे कर एक वरकर को जबरदस्ती शेरिंग मशीन पर बैठाया गया। शाम को हाथापाई हुई और दूसरे दिन बल्लबगढ़ पुलिस तीन मजदूरों को पकड़ कर ले गई। विक्टोरा टूल्स के सब मजदूर इकट्ठे हो कर थाने पहुँचे, पुलिस ने गिरफ्तार मजदूर छोड़ दिये। इस घटनाक्रम के बाद मजदूरों में किसी यूनियन से जुड़ने पर चर्चा आरम्भ हुई एक वरकर ने मैनेजमेंट को भेद बता दिया और हिसाब ले कर चला गया। मैनेजमेन्ट ने जान-बूझ कर 7 सितम्बर को वेतन नहीं दिया। लेबर इन्सपैक्टर ने इस बाबत शिकायत पर 17 सितम्बर को बात-चीत द्वारा लीपा-पोती की। और मैनेजमेन्ट ने 18 सितम्बर को फैक्ट्री में झगड़ा करवा कर, चाकू मारने की झूठी रिपोर्ट पर सरकारी डाक्टरों से मोहर लगवा कर पाँच मजदूर गिरफ्तार करवा दिये 24 सितम्बर को यह मजदूर जमानत पर छूटे और मैनेजमेन्ट के तीन लोग गिरफ्तार किये गये। 25 सितम्बर को विक्टोरा टूल्स के मजदूरों ने एक यूनियन का झन्डा फैक्ट्री गेट पर लगा दिया। 15 अक्टूबर को मजदूरों ने अपनी डिमान्डें मैनेजमेंट को पेश की। 20 को मैनेजमेन्ट ने डिमान्डों पर बातचीत की लेकिन बहाना बना कर फैसला 21-23 के लिये टाल दिया। 24 अक्टूबर को कुछ बातचीत के बाद मैनेजमेंट ने गो स्लो का नोटिस लगा दिया और 3 नवम्बर तक ऐसे नोटिस लगाती रही जब कि मजदूरों ने कोई गो स्लो नहीं किया था। 9 नवम्बर को मैनेजमेंट ने पाँच मजदूरों को डिसमिस कर दिया। तब मजदूरों ने अपने साथियों को काम पर लेने के लिये स्लो डाउन किया। 11 नवम्बर को मैनेजमेन्ट ने मजदूरों से अन्डरटेकिंग माँगी और मना करने पर गेट के अन्दर नहीं जाने दिया। टूल रूम के मजदूरों से मैनेजमेन्ट ने अन्डरटेकिंग नहीं माँगी। इस प्रकार सौ के लगभग मजदूरों में से 70 मजदूर 11 नवम्बर से गेट के बाहर हैं। लेबर डिपार्टमेन्ट में पाँचवी तारीख पर जा कर 28 नवम्बर को मैनेजमेन्ट हाजिर हुई और आठ मजदूरों को छोड़ कर बाकी को काम पर लेने, डिमान्डों पर बात करने तथा आगे से गाली-गलोज नहीं करने की पेशकश रखी। सब मजदूरों को काम पर लेने को मजदूरों ने अपनी बुनियादी शर्त बताया। समझौता नहीं हुआ और मजदूरों का संघर्ष जारी है। विक्टोरा टूल्स में भारतीय और नेपाली मजदूर कन्धे से कन्धा मिला कर डटे हैं और मजदूर एकता की एक अच्छी मिसाल पेश कर रहे हैं।

लेबर डिपार्टमेंट वाली भागदौड़ और फैक्ट्री गेट पर बैठने से ज्यादा कुछ नहीं होगा, बल्कि यह मजदूरों को थकाने वाले कदम ही अधिक है। इसलिये इस संघर्ष में सफलता के लिये हमारे विचार से विक्टोरा टूल्स के मजदूरों को अपनी ताकत बढाने वाले कदमों पर विचार करना चाहिये। एक कदम हर रोज सुबह आठ बजे फैक्ट्री गेट से बल्लबगढ कोर्ट तक जलूस हो सकता है। पाँच-सात दिन तक लगातार स्वयं ऐसे जलूस निकाल कर यह मजदूर अपने परिवार के सदस्यों व अन्य मजदूरों को इन जलूसों में शामिल करके मजदूर पक्ष की ताकत बढ़ा सकेंगे। पूँजीवादी पक्ष जिसमें विक्टोरा मैनेजमेन्ट के साथ मैनेजमेन्टों की एशोसियेशन, पुलिस, लेबर डिपार्टमेन्ट, एम पी-डी सी, सरकार आदि हैं उसके खिलाफ बिखरी पड़ी मजदूर पक्ष की ताकत को इकट्ठा करने के लिये कदम उठा कर ही विक्टोरा टूल्स के मजदूर सफलता की राह पर बढ़ सकेंगे।

अमरीकी बैंकों में संकट

प्रायवेट की बीमारी की जड़ और सरकारी को स्वास्थ्य की राह में एक बड़ा कदम मानने के काफी समय से जारी चलन के स्थान पर आजकल "प्रायवेट" को स्वास्थ्यवर्धक टानिक और सरकारी को बीमारी का घर पेश करना फैशन में है। इस हकीकत को सामने लाने के लिये कि संकट सरकारी अथवा "प्रायवेट" वाले रूपों मात्र का नहीं बल्कि सम्पूर्ण पूँजीवादी व्यवस्था का है, यहाँ हम अमरीका में बैंकों की आज हालत की एक झलक प्रस्तुत कर रहे हैं। साथ ही, "प्रायवेट" के स्वर्ग, अमरीका में बैंकों के मामले में अमरीका सरकार का भारी वजन स्पष्ट तौर पर सामने आता है।

1989 में अमरीका में 825 खरब रुपये सम्पत्ति वाले 12,706 व्यवसायिक बैंक थे जिनमें जमा राशियों का अमरीका सरकार ने बीमा किया हुआ है। इनमें से 1100 बैंक समस्या सूची पर है। अमरीका के दस सबसे बड़े बैंकों में से पाँच ने इस वर्ष घाटा दिखाया। 2 खरब 50 अरब रुपयों से अधिक सम्पत्ति वाले बड़े बैंकों में से एक चौथाई बैंकों ने इस वर्ष घाटा दिखाया है।

अमरीका सरकार की रिपोर्टों के मुताबिक भी इस समय अमरीका बैंक विकट स्थिति का सामना कर रहे हैं। "नरम" मन्दी रही तो इस वर्ष 15 खरब रुपये सम्पत्ति वाले 180 और बैंकों का दिवाला निकलेगा तथा अगले वर्ष 7 खरब 50 अरब रुपये सम्पत्ति वाले 160 और बैंक दिवालिया होंगे। मन्दी कुछ गहरा गई तो इस वर्ष ही 22 खरब 50 अरब रुपये सम्पत्ति वाले 230 बैंकों का जनाजा निकलेगा और अगले वर्ष 17 खरब 50 अरब रुपये सम्पत्ति वाले 210 और बैंक बन्द होंगे। वैसे पूँजीवादी बुद्धिजीवियों के अनुसार "नरम" या उससे मिलती जुलती नहीं बल्कि बहुत भारी मन्दी की स्थितियाँ बन गई है।

अमरीका में बैंकों को दिवालिया होने से बचाने के लिये सरकार द्वारा बनाये गये बैंक बीमा फण्ड में इस समय कोई फण्डस नहीं है। अमरीका सरकार के सब धड़ों के बड़े लोगों का बैंकों से नजदीकी रिश्ता है इस लिये वे बैंक बीमा फण्ड के लिये 6 खरब 25 अरब रुपये की जुगाड़ में पापड़ बेल रहे हैं।

बैंकों की यह हालत अचानक खराब नहीं हुई है। 1986 के बाद से अमरीका में बैंकों के दिवाला निकलने की रफ्तार बहुत बढ़ गई है—इन पाँच वर्षों में दिवाला निकले बैंकों की संख्या इनसे पिछले पचास वर्षों में दिवाला निकले बैंकों की संख्या से अधिक है। पिछले चार वर्षों में तो ऐसे बड़े बैंकों का भी दिवाला निकल गया है जिनके बारे में दावा किया जाता था कि वे इतने बड़े हैं कि उनका दिवाला नहीं निकल सकता। (सामग्री हमने अक्टूबर के टाईम्स आफ इंडिया से ली है।)

माल उत्पादन, विशेषकर पूँजीवादी माल उत्पादन की जरूरतों ने बैंक प्रणाली को विकसित किया। पूँजीवादी व्यवस्था के संकटों ने सामाजिक जीवन में बैंकों की भूमिका को शक्तिशाली बनाया। यह सही है कि बैंकों के कामकाज में गड़बड़ियाँ पूँजीवादी व्यवस्था में जब-तब भूचाल ला देती है लेकिन आम-तौर पर यह सामाजिक जीवन के भौतिक उत्पादन की पूँजीवादी प्रणाली के संकट ही होते हैं जो कि अन्य क्षेत्रों की तरह बैंकों की लड़खड़ाहट की भी जड़ में होते हैं। और आज विश्व पूँजीवादी व्यवस्था में अमरीकी बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

पूँजीवादी व्यवस्था के महामन्दी/ग्रेट डिप्रेशन के दौर वाले संकट ने अमरीका की बैंकिंग प्रणाली को इस कदर लड़खड़ा दिया था कि अमरीका सरकार को 1933 में चार दिन के लिये सब बैंक बन्द करने पड़े थे। इस समय वाले पूँजीवादी व्यवस्था के संकट ने एक तरफ जहाँ रूस आदि राज्य पूँजीवादी किलों की ईंट से ईंट बजा दी है वही अमरीकी बैंक इसकी वजह से 1933 की बैंक बन्दी से भी विकट स्थिति का सामना कर रहे है। महामन्दी वाले संकट से पैदा हुई हड़कम्प ने 1939 में दूसरे पूँजीवादी विश्वयुद्ध को जन्म देकर पाँच करोड़ मनुष्यों की बलि ली थी। आज राज्य-पूँजीवादी किलों का ढहना, अमरीका बैंकों का दिवालिया होना उस सिलसिले के अंग हैं जिसने विगत में भयंकर पूँजीवादी खूंखारों को जन्म दिया। यह इसलिये है कि हम पूँजीवादी व्यवस्था के गहराते संकट से पार पाने के लिये आज क्रांतिकारी मजदूर आन्दोलन के विकास की अरजेन्ट आवश्यकता को बार-बार प्रस्तुत करते हैं।

केल्विनेटर में धक्का

कम वेतन और अधिक वर्क लोड के खिलाफ भड़के मजदूरों के असन्तोष को दबाने के लिये मैनेजमेंट ने इस वर्ष 2 अक्टूबर को दुबारा लाकआऊट किया। इस हमले के खिलाफ कदम उठाने के लिये आम मजदूर, लीडरों का मुंह ताकते ही रह गये। लीडर लोग पहले तो चार-पाँच लाख के चन्दे को ठिकाने लगाने में रहे और फिर उनमें जूतम-पजार शुरू हो गई। इन हालात में हमले के खिलाफ हाथ पर हाथ धरे बैठे मजदूरों को दबाने में मैनेजमेंट कामयाब हुई और 3 दिसम्बर से तालाबन्दी खत्म कर दी।

मजदूरों की अन्धी एकता में भी बल होता है पर यह मैनेजमेंट को झकझोर ही सकता है, मजदूरों के हितों को आगे नहीं बढ़ा सकता। किसी मसीहा पर आस तो मजदूरों की बरबादी की राह है ही, लीडरों को जनरलों के तौर पर लेना और उनके हुक्म का इन्तजार करना भी मजदूरों के लिये नुकसान ही नुकसान लिये है। आने वाले दिनों में मजदूरों के असन्तोष को बढ़ाने वाले हालात केल्विनेटर में बढ़ेंगे। ऐसे में सचेत सगठित संघर्ष करना मजदूर हित में आवश्यक होगा—इस सम्बन्ध में केल्विनेटर मजदूरों से विचार-विमर्श का हम स्वागत करेंगे।

- आटोपिन ग्रुप के मथुरा रोड स्थित सिराको आटो प्लान्ट में मैनेजमेन्ट ने दस नवम्बर से तालाबन्दी कर दी है।
- गेडोर उर्फ झालानी टूल्स में आल इंडिया "हड़ताल" के दिन, 29 नवम्बर को रैस्ट रहा और उसके बदले में सन्डे वर्किंग डे।
- 24 सैक्टर स्थित इनवैल इंजिनियरिंग के मजदूर संघर्ष की राह पर कदम उठा रहे हैं।
- स्टेरिबेयर-स्टेरिप्लेट के मजदूरों को मैनेजमेन्ट ने फैक्ट्री गेट पर रोक दिया है।
- यूनिवर्सल इंजिनियरिंग के मजदूर फैक्ट्री गेट पर धरने पर बैठे हैं।

हमारे लक्ष्य हैं:— 1. मौजूदा व्यवस्था को बदलने के लिये इसे समझने की कोशिशें करना और प्राप्त समझ को ज्यादा से ज्यादा मजदूरों तक पहुचाने के प्रयास करना। 2. पूँजीवाद को दफनाने के लिए जरूरी दुनियां के मजदूरों की एकता के लिये काम करना और इसके लिये आवश्यक विश्व कम्युनिस्ट पार्टी बनाने के काम में हाथ बटाना। 3. भारत में मजदूरों का क्रान्तिकारी सगठन बनाने के लिये काम करना। 4. फरीदाबाद में मजदूर पक्ष को उभारने के लिये काम करना।

समझ, सगठन और संघर्ष की राह पर मजदूर आन्दोलन को आगे बढ़ाने के इच्छुक लोगों को ताल-मेल के लिये हमारा खुला निमन्त्रण है। बातचीत के लिये बेझिझक मिलें। टीका टिप्पणी का स्वागत है—सब पत्रों के उत्तर देने के हम प्रयास करेंगे।

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं सम्पादक शेर सिंह के लिए उत्तरांचल प्रिन्टर्स, फरीदाबाद से मुद्रित